



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 294]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 16, 2017/कार्तिक 25, 1939
No. 294]	NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 16, 2017/KARTIKA 25, 1939

विधि और न्याय मंत्रालय

(न्याय विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 2017

सं. 19018/01/2017.—न्याय उच्चतम न्यायालय ने 1989 की रिट याचिका संख्या 1022 में 1992 की पुनरीक्षा याचिका संख्या 249 में 24-08-1993 को दिए गए अपने निर्णय द्वारा दिए गए एक निदेश के अनुपालन में राज्यों और संघशासित क्षेत्रों में न्यायिक अधिकारियों की परिलब्धियों और सेवा शर्तों के मौजूदा ढांचे की जांच करने के लिए उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति के जगन्नाथ शेटी की अध्यक्षता के तहत 21-03-1996 को पहला राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (एफ़एनजेपीसी) गठित किया था। इस आयोग ने 11-11-1999 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

2. तदन्तर, छठवें वेतन आयोग के कार्यान्वयन के फलस्वरूप अखिल भारत न्यायाधीश संघ ने शेटी कमीशन रिपोर्ट के आधार पर देशभर की अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों के वेतन, भत्तों के संशोधन के लिए उच्चतम न्यायालय में उपर्युक्त याचिका में एक आईए (संख्या 244, 2009) दायर की। उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक अधिकारियों के वेतनमानों और भत्तों तथा अन्य परिलब्धियों के संबंध में न्यायाधीश शेटी आयोग द्वारा पहले से ही की गई सिफ़ारिशों को ध्यान में रखते हुए उचित सिफ़ारिशें करने के लिए उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश, न्यायमूर्ति ई. पद्मानभन को एक सदस्यीय समिति के रूप में नियुक्त किया। इस समिति ने जुलाई, 2009 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे संघ शासित क्षेत्रों में न्यायिक अधिकारियों के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा कार्यान्वित किया गया था।

3. अब भारत के उच्चतम न्यायालय ने अखिल भारत न्यायाधीश संघ बनाम भारत संघ व अन्य द्वारा दायर रिट याचिका संख्या 643/2015 में 09 मई, 2017 के अपने आदेश द्वारा निदेश दिया है कि भारत में अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों के वेतनमानों, परिलब्धियों और सेवा-शर्तों की पुनरीक्षा करने के लिए एक न्यायिक वेतन आयोग का गठन किया जाए।

4. उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त निदेश के अनुपालन में यह निर्णय लिया गया है कि एक नया राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग, जो कि दूसरा राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग के नाम से जाना जाएगा, नियुक्त किया जाए, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:—

- अध्यक्ष - श्री न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) पी. वेंकटरामा रेड्डी, भारत के उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश।
- सदस्य - श्री न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) आर. बसंत, केरल उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश और भारत के उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता।

- (iii) सदस्य-सचिव - आयोग द्वारा चुना जाएगा जो अधिमानतया कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी होगा। यदि आयोग किसी राज्य के सेवारत न्यायिक अधिकारी को चुनने का निर्णय लेता है तो संबंधित उच्च न्यायालय और संबंधित राज्य इस प्रकार के अधिकारी की सेवाओं को उपलब्ध कराएंगे और इस प्रकार के अधिकारी को आयोग में प्रतिनियुक्ति पर माना जाएगा।

5. भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा इस आयोग की सहायता के लिए इसके एक अतिरिक्त महा न्यायभिक्षु की सेवाओं को उपलब्ध करना होगा।

6. यह आयोग कार्य को पूरा करने के उद्देश्य के लिए आवश्यक कर्मिकों सहित ढांचागत समर्थन की इसकी आवश्यकताओं को यदि कोई हो विधि और न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग) को इंगित करेगा।

7. इस आयोग की संदर्भ शर्तें निम्नलिखित प्रकार से होंगी:—

- क. ऐसे सिद्धांतों को विकसित करना जो देशभर में अधीनस्थ न्यायपालिका से संबंधित रखने वाले न्यायिक अधिकारियों के वेतन और अन्य परिलब्धियों के ढांचे को शासित करे।
- ख. राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में न्यायिक अधिकारियों को उन्हें उपलब्ध उन समस्त लाभों को ध्यान में रखते हुए उन्हें मिलने वाली परिलब्धियों और उनकी सेवा-शर्तों के मौजूदा ढांचे की जांच करना और अन्य संगत कारकों को मद्देनजर रखते हुए पेंशन आदि जैसे सेवानिवृत्ति के लाभों सहित अन्य सिविल सर्वेण्ट की तुलना में अधीनस्थ न्यायिक सेवा से संबंधित अधिकारियों के बीच वेतन ढांचे में मौजूदा तुलनात्मकता के लिए और इस संबंध में शिकायतों का निपटान करने के लिए तंत्र बनाने के लिए उचित सिफारिशें करना।
- ग. कार्य की पद्धति और कार्य के वातावरण तथा और वस्तु के रूप में वे विभिन्न भत्ते और लाभ जो न्यायिक अधिकारियों को वेतन के अलावा प्राप्त होते हैं, की जांच करना और न्यायपालिका के आकार को इष्टतम करते हुए न्यायिक प्रशासन में दक्षता संवर्धन को ध्यान में रखते हुए उनका औचित्यकरण और सरलीकरण करने के लिए सुझाव देना और पिछली सिफारिशों के कार्यान्वयन में सृजित असंगतताओं को दूर करना।
- घ. इस प्रकार की अन्तरिम राहत पर विचार व सिफारिश करना जो वह राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के न्यायिक अधिकारियों की सभी श्रेणियों के लिए न्याय संगत और उचित समझे। यह अन्तरिम राहत, यदि इसकी सिफारिश की जाती है, तो इसे उस पैकेज के प्रति पूरी तरह समायोजित व उसमें शामिल किया जाना होगा जो इस आयोग की अंतिम सिफारिशों पर न्यायिक अधिकारियों को देय हो सके।
- ङ. अधीनस्थ न्यायपालिका की सदस्यों के वेतन और सेवा-शर्तों की एक स्वतंत्र आयोग, जो विशेषरूप से इस उद्देश्य के लिए गठित हुआ हो, द्वारा आवधिकरूप से समीक्षा के लिए एक स्थायी तंत्र स्थापित करने के लिए तंत्र की सिफारिश करना और इस प्रकार के आयोग की संरचना में न्यायपालिका की ओर से पर्याप्त प्रतिनिधित्व परिलक्षित होना चाहिए।

8. इस कार्य को प्राप्त करने के लिए यह आयोग अपनी स्वयं की प्रक्रियाओं को विकसित करेगा और आवश्यक पद्धतियाँ बनाएगा। यह इस प्रकार के सलाहकारों, संस्थागत परामर्शदाताओं और विशेषज्ञों को नियुक्त कर सकता है जो वह किसी विशेष उद्देश्य के लिए आवश्यक समझे। सभी राज्य सरकारें, संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन और केंद्र सरकार के मंत्रालय/विभाग इस आयोग द्वारा यथापेक्षित सूचना, दस्तावेज और अन्य सहायता देंगे।

9. यह आयोग, राज्य सरकारों को अपनी सिफारिशें देगा और भारत के उच्चतम न्यायालय और विधि एवं न्याय मंत्रालय को अधिमानतया 18 महीनों की एक समयावधि के अंतर्गत इसकी प्रति प्रस्तुत करेगा। यह, सिफारिशों को अंतिम रूप दिए जाने पर किसी भी मामले के बारे में रिपोर्ट भेजने की बात पर, यदि आवश्यक समझे, विचार कर सकता है।

आदेश दिया जाता है इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों एवं अन्य जो भी संबंधित हों, को भेजी जाए।

डॉ. आलोक श्रीवास्तव, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE**(Department of Justice)****RESOLUTION**

New Delhi, the 16th November, 2017

No. 19018/1/2017-Jus.—Pursuant to a direction of the Supreme Court of India *vide* its judgement delivered on 24.8.1993 in Review Petition No. 249 of 1992 in W.P. No. 1022 of 1989, First National Judicial Pay Commission (FNJPC) under the chairmanship of Justice K Jagannatha Shetty, former Judge of the Supreme Court of India was constituted on 21.03.1996 to examine the present structure of emoluments and conditions of service of judicial officers in the States and UTs. The Commission submitted its report on 11.11.1999.

2. Subsequently, consequent upon implementation of 6th CPC, All India Judges Association filed an I.A. (No. 244 of 2009) in the aforesaid writ petition in the Supreme Court praying for revision of salaries, allowances of judicial officers of subordinate judiciary throughout the country based on the Shetty Commission Report. Supreme Court appointed Justice E. Padmanabhan, a retired High Court Judge as one member Committee to make suitable recommendations having regard to the recommendations already made by the Justice Shetty Commission in respect of the pay scales and allowances and other perquisites of the Judicial Officers. The Committee submitted its report in July, 2009 which was implemented by the Union Government in respect of judicial officers in the UTs.

3. Now, *vide* its order dated 9th May, 2017 in Writ Petition No. 643/2015 filed by All India Judges Association vs. Union of India & others, Supreme Court of India has directed to appoint a Judicial Pay Commission to review the pay scales, emoluments and service conditions of the Judicial Officers of Subordinate Judiciary in India.

4. In pursuance of the above direction of Supreme Court of India, it has been decided to appoint a fresh National Judicial Pay Commission, to be known as Second National Judicial Pay Commission, comprising the following:—

- (i) Chairman - Mr. Justice (Retd.) P. Venkatarama Reddi, former Judge of Supreme Court of India.
- (ii) Member - Mr. Justice (Retd.) R. Basant, former Judge of Kerala High Court and Senior Advocate of Supreme Court of India.
- (iii) Member-Secretary - (to be chosen by the Commission, preferably a Judicial Officer either in service or retired. In case the Commission decides to choose a serving Judicial Officer of any State, the concerned High Court and the State will make available the services of such an officer and treat such officer to be on deputation to the Commission.)

5. Services of one of its Additional Solicitors General will be made available to assist the Commission by Department of Legal Affairs, Ministry of Law & Justice in pursuance to the direction of Supreme Court of India.

6. The Commission will indicate to the Ministry of Law & Justice (Department of Justice) as to its requirements of infrastructural support, including the personnel, if any, necessary for the purpose of carrying on the task.

7. The Terms of Reference of the Commission will be as follows:—

- a. To evolve the principles which should govern the structure of pay and other emoluments of Judicial Officers belonging to the subordinate Judiciary all over the country.
- b. To examine the present structure of emoluments and conditions of service of Judicial Officers in the states and UT's taking into account the total packet of benefits available to them and make suitable recommendations including post retirement benefits such as pension etc. having regard among other relevant factors, to the existing relativities in the pay structure between the officers belonging to subordinate judicial services vis-à-vis other civil servant and mechanism for redressal of grievances in this regard.

- c. To examine the work methods and work environment as also the variety of allowance and benefits in kind that are available to Judicial Officers in addition to pay and to suggest rationalisation and simplification thereof with a view to promoting efficiency in Judicial Administration, optimizing the size of judiciary etc. and to remove anomalies created in implementation of earlier recommendations.
 - d. To consider and recommend such interim relief as it considers just and proper to all categories of Judicial Officers of all the States/Union Territories. The interim relief, if recommended, shall have to be fully adjusted against and included in the package which may become admissible to the Judicial Officers on the final recommendations of the Commission.
 - e. To recommend the mechanism for setting up of a permanent mechanism to review the pay and service conditions of members of sub-ordinate judiciary periodically by an independent commission exclusively constituted for the purpose and the composition of such commission should reflect adequate representation on behalf of the judiciary.
8. The Commission will devise its own procedures and formulate modalities necessary for accomplishing the task. It may appoint such advisers, institutional consultants and experts as it may consider necessary for any particular purpose. It may call for such information and take such evidence as it may consider necessary. All State Governments, UT Administrations and the Ministries/Departments of the Central Government will furnish such information, documents and other assistance as required by the Commission.
9. The Commission will make its recommendations to the State Governments and submit a copy of the same to the Supreme Court of India and Ministry of Law & Justice preferably within a period of 18 months. It may consider, if necessary, sending reports on any of the matters as and when the recommendations are finalized. The Commission shall be at liberty to approach Apex Court to seek any further clarification or direction.

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India,

Ordered also that a copy of the Resolution be communicated to the Ministries/Depts. of the Govt. of India/State Govts./UT Administrations and all other concerned.

Dr. ALOK SRIVASTAVA, Secy.